

अलवर में नगरीय विकास जनित पर्यावरणीय समस्याओं का भौगोलिक अध्ययन

सपना कल्याण , शोधार्थी , भूगोल विभाग , महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय , बीकानेर , राजस्थान

डॉ. अंजू ओझा, सहायक आचार्य , भूगोल विभाग , राजकीय लोहिया महाविद्यालय , चुरू , राजस्थान

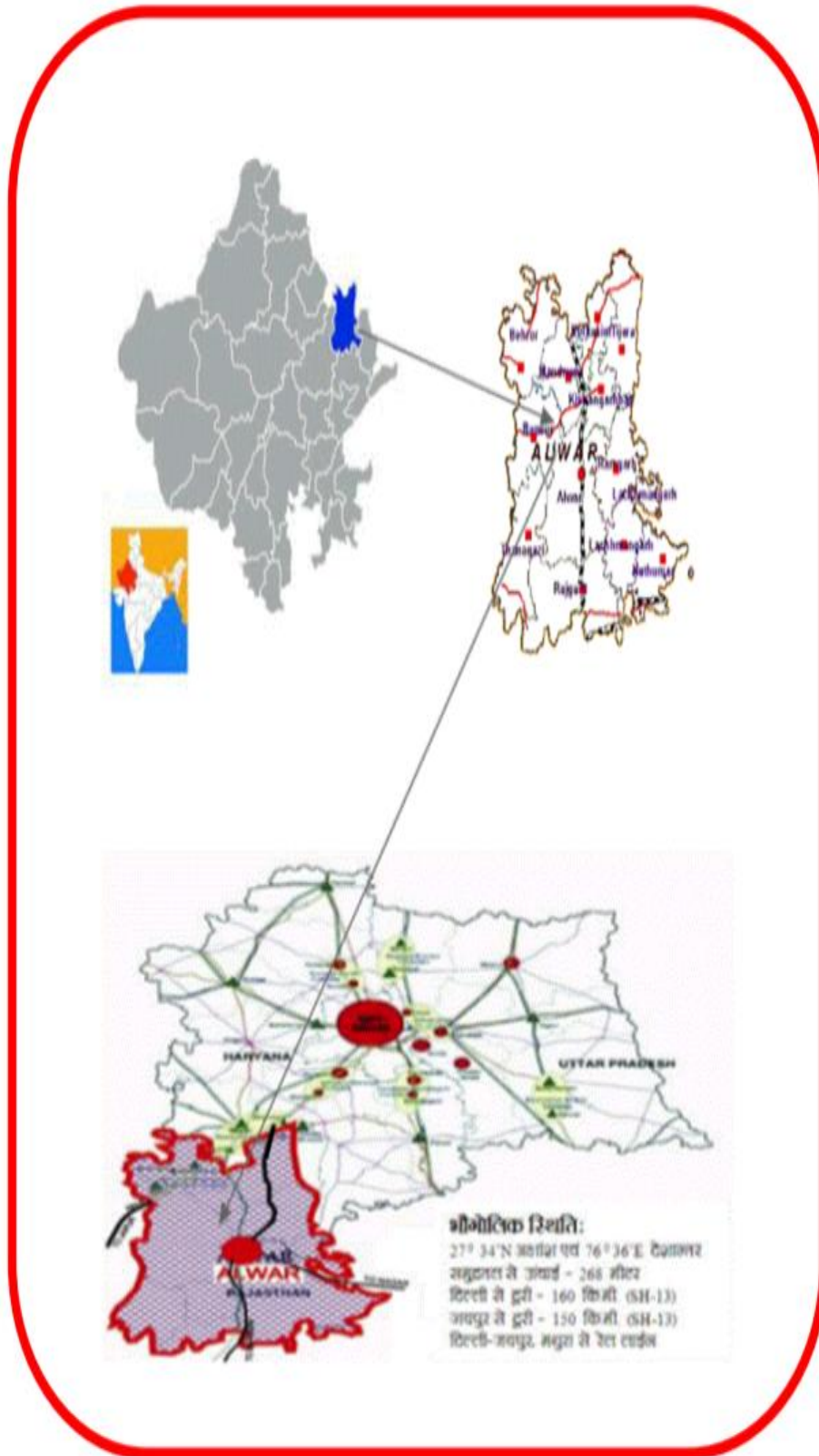
शोध सारांश

शहरीकरण ने विशेष रूप से विकासशील देशों की सरकार के लिए कई समस्याओं को अपने प्रभाव में ला दिया है। हालांकि, उच्च आय शहरी निवासियों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है, फिर भी शहरी गरीबी और बेरोजगारी और प्रदूषण और भीड़भाड़ से जुड़ी कई समस्याएं शहरी विफलताओं के सबसे उल्लेखनीय संकेतक हैं। वर्तमान अध्ययन में शहरी अलवर की वर्तमान स्थिति पर जोर दिया गया है। नए चरण में नई चुनौतियाँ आती हैं। शहरीकरण का एक तरह से दुष्प्रभाव होता है जब नियोजन जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को पूरा नहीं करता है जैसे "ईंधन के बिना एक वाहन इस तथ्य के बावजूद कुछ भी नहीं है कि यह कितना भव्य है"। अध्ययन बदलते चरण से संबंधित है। अलवर, अलवर का शहरी होना अपने आप में एक चुनौती है और प्रबंधन द्वारा की गई उचित योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता है अतः प्रस्तुत शोध पत्र में अलवर में नगरीय विकास जनित पर्यावरणीय समस्याओं का भौगोलिक अध्ययन किया गया है।

मुख्य बिन्दु :-शहरी, शहरीकरण, मास्टर प्लान, प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं, अलवर में शहरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे और उनके समाधान।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय :-

अलवर शहर उत्तर-पूर्वी राजस्थान में 27° 32' 30" उत्तर अक्षांश और 76° 37' 30" पूर्व देशांतर पर स्थित है। शहर में 48.14 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है और इसमें 3,15,310 लोगों की आबादी है (जनगणना, 2011)। पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। अलवर रेलवे और सड़कों से नई दिल्ली और जयपुर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पहुँचा जा सकता है। इसकी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है और पर्यटन, व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र है



उद्देश्य :-

इस पत्र का उद्देश्य अलवर शहर में शहरी क्षेत्र की पर्यावरणीय समस्या और उसके प्रभावों की जांच करना है । यह शोध पत्र पर्यावरण समस्या से निपटने के लिए सरकार की भूमिका की भी समीक्षा करता है। प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करना और उचित शहरी नियोजन के कार्यान्वयन की आवश्यकता ।

परिकल्पना :-

अलवर में नगरीय विकास से पर्यावरणीय समस्या बढ़ती जा रही है ।

आँकड़ों का संग्रह व विधितन्त्र :-

यह वर्तमान शोध पत्र द्वितीयक प्रकार के डेटा पर आधारित है जो मूल रूप से यूआईटी अलवर जैसे द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किया गया है और उपयोग की जाने वाली इनपुट विधि पेपर है। प्रत्येक आइटम का उचित विश्लेषण डेटा को ग्राफ और टेबल की मदद से अच्छी तरह से दर्शाया गया है। उपयोग की जाने वाली सुविधाओं का उपयोग शोध पत्र में किया गया है।

यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक डेटा को वर्तमान भूमि उपयोग श्रेणियों, संरचना और संबंधित समस्याओं और मुद्दों के आधार मानचित्र और गूगल इमेजरी का उपयोग करके क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किया गया है। भूमि उपयोग, इतिहास, जनसंख्या, औद्योगिक और आधारभूत सुविधाओं, और अन्य सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं की जानकारी राज्य और नगरपालिका स्तर पर अलवर सहित विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त की गई है ।

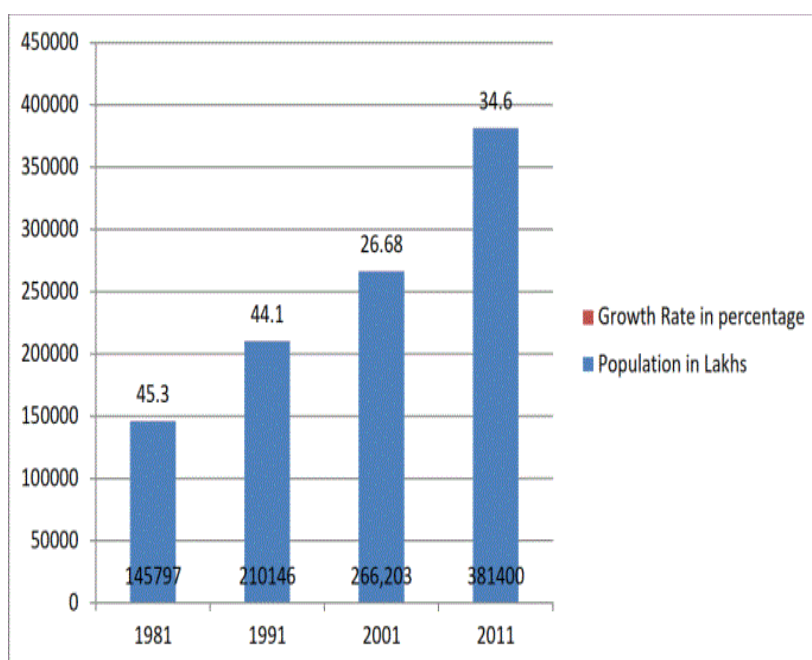
आँकड़ों हेतु संग्रहालय, अलवर; राजस्थान राज्य अभिलेखागार, नगर नियोजन विभाग, अलवर; पीडब्ल्यूडी, अलवर। विश्लेषण और व्याख्या के लिए। भूमि उपयोग से संबंधित प्रमुख मुद्दों और उनके सामने आने वाली समस्याओं और नियोजन की आवश्यकता को समझने के लिए वाणिज्यिक डेवलपर्स, प्रोफेसर्स, राजनेताओं, शिक्षाविदों, इंजीनियरों, उद्योगपतियों, स्थानीय लोगों और नियोजन अधिकारियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से क्षेत्र सर्वेक्षण भी शामिल था। शहर के मास्टर प्लान को आधार बनाया गया है।

अलवर में शहरीकरण के चरण एवं समस्याएं :-

अलवर में विकास की तेज गति 1980 के दशक के बाद जनसांख्यिकीय संरचना, बाजारों, शहरी स्थानों और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ इसके इलाकों और परिधीय बस्तियों के विकास के संदर्भ में शुरू हुई।

एनसीआर के लिए 1985 में तैयार की गई योजना के अनुसार, अलवर और भिवाड़ी को क्षेत्रीय केंद्रों के रूप में पहचाना गया था और प्राथमिकता के आधार पर उद्योगों और अन्य आर्थिक गतिविधियों की स्थापना के लिए विकसित किया जाना था (जीओआर 2011)। इस तरह के नियोजित प्रयासों के साथ, अलवर एनसीआर के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और उपग्रह शहर के रूप में उभरने लगा और इसने एक उत्पाद के साथ-साथ राज्य की प्रक्रियाओं और बाजार के पैतरेबाज़ी द्वारा एक प्रक्रिया के रूप में अपना आकार प्राप्त किया (श्रीवास्तव) , 2009)।

सरकार के विभिन्न प्रयासों जैसे उद्योग के विकास और शहर में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण शहर की आबादी में वृद्धि देखी गई। शहर ने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों (यूआईटी 2014) से प्रवासियों को आकर्षित किया।



1981 में जनसंख्या 38.10 प्रतिशत से बढ़कर 45.30 प्रतिशत, 1991 में 44.10 प्रतिशत और बाद में 2001 और 2011 में क्रमशः 26.68 प्रतिशत और 28.24 प्रतिशत तक कम हो गई। अंत में, यह अलवर मेट्रोपॉलिटन एरिया में चार गांवों (मन्नका, दिवाकरी, बेलाका, भुगोर) को शामिल करने के साथ है, 2011 में अलवर शहर की पूर्ण विकास दर 34.60% (यूआईटी 2014) तक पहुँचती है, 2011 की जनगणना के दौरान परिधि पर स्थित है। अलवर शहर के किनारे अलवर शहर की आबादी के हिस्से के रूप में गिने जाते हैं।

अलवर को न केवल एनसीआर दिल्ली के मास्टर प्लान (लाल 2001) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शहर में बुनियादी ढांचे, परिवहन, उद्योग आदि के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए 2001 में जीओआर स्वयं अपनी मास्टर प्लान के साथ आया था। योजना में वर्ष 2031 के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्तमान में, शहर का शहरी क्षेत्र 49 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से औद्योगिक (26b) और आवासीय (46b) क्षेत्र कुल भूमि का 72b (यूआईटी 2014) कवर करते हैं।

शहरी होने की प्रमुख चिंता भूमि की बढ़ती लागत और अलवर में शहरी भूमि की पहुंच में है। अलवर में जमीन की कीमत सबसे महंगी प्रवृत्ति के बाद शहर के बीचोबीच पाई जाती है जहां शहरी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा सबसे अच्छा है। अलवर को क्षैतिज रूप से तीन भागों में विभाजित करने पर मध्य भाग में अधिकतम लागत आती है जो अन्य दो पक्षों पर घट जाती है, यानी सघन रूप से निर्मित आंतरिक भाग और कम विकसित बाहरी भाग।

रोड नं. 2, प्रतापबास, जुबलीबास और उच्च भूमि मूल्य की विशेषता वाले प्रमुख चौराहों पर भूमि के लाभदायक रिटर्न लेने के लिए असंवैधानिक साबित होते हैं। भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक में स्थानांतरित हो गया है। यह प्रमुख चौराहों पर और बाहरी हिस्से में दिल्ली और जयपुर सड़कों के साथ अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। रिहायशी कॉलोनियों के बीच खाली भूखंड, भूमि भूखंडों के आकार के साथ-साथ निर्मित संरचनाओं के आकार में कमी और अस्पष्ट सौंदर्य और स्थापत्य शैली को अपनाने में वृद्धि। जैसे-जैसे जमीन की कीमतें बढ़ती हैं, समाज के अन्य तबके सीमा पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि जमीन की कीमतें तुलनात्मक रूप से कम हैं। शहर का निर्मित क्षेत्र क्षैतिज रूप से बाहरी हिस्सों की सस्ती कृषि भूमि के करीब पहुंच रहा है। शहरी भूमि उपयोग में काफी हद तक वृद्धि, दिल्ली रोड के साथ पूर्व में ड। की ओर तेजी से हो रहा है। भविष्य में, इसका लोगों और उद्योगों दोनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। एमआईए के विकास और शहर में उच्च भूमि मूल्य ने दिल्ली रोड पर शहरी फैलाव के विकास को प्रेरित किया है, जो कम घनत्व, छलांग विकास और बाहरी विस्तार की विशेषता है।

कृषि भूमि, जो शहर में आवासीय भूमि की तुलना में सस्ती है और मुख्य सड़कों पर नगर निगम के करों से मुक्त है, भूमि पर पैसे के निवेशकों के लिए चुंबकीय गुण प्राप्त कर चुकी है और जहां ऐसा कोई नियंत्रण कानून लागू नहीं है। विकास के कम घनत्व के पैटर्न ने भूमि के दुरुपयोग को भी प्रोत्साहित किया है क्योंकि बड़ी मात्रा में कृषि भूमि खाली या अनुपयोगी छोड़ दी जाती है। इस प्रकार की बेतरतीब और अनियंत्रित वृद्धि होने पर शहर के बाहरी हिस्से में होने वाली झुग्गी बस्तियों के निर्माण के लिए ऐसी स्थितियाँ अनुकूल होती हैं। वर्षों तक बना रहता है।

यातायात की बाधाएं: त्रिपोलिया शहर में एक ऐसा उदाहरण है जहां सोमवार एक भारी दिन है। सुबह दोपहिया वाहनों वाले भक्तों को अपनी अत्यधिक भक्ति के साथ शांति से मंदिर में प्रचार करने के लिए जगह नहीं मिली। यह मंदिर प्रतिदिन कई भक्तों को आकर्षित करता है लेकिन सोमवार को सौर मंडल का सूर्य साबित होता है। पार्किंग सुविधा की कमी से दैनिक आधार पर भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम होता है। 2011 में जनसंख्या में वृद्धि के कारण।

केदलगंज भी उसी अनुभव को साझा करता है क्योंकि क्षेत्र में छोटे पैमाने और घरेलू उद्योगों के स्थान विशेष रूप से टेली, घानी और खांडसारी उद्योग अब स्थान के लिए अनुपयुक्त साबित हुए हैं। जगह की कमी आसपास के शोर और उपद्रव के कारण निवासियों की वांछित गोपनीयता और शांति में बाधा उत्पन्न करती है।

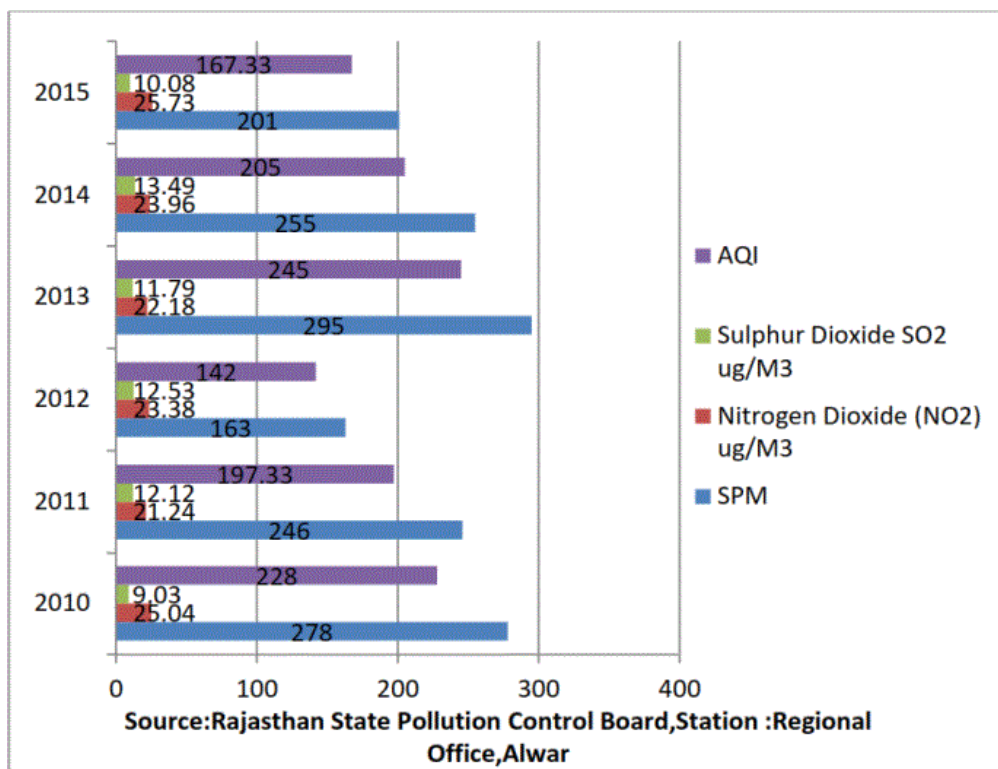
घंटाघर सब्जी मंडी और केदलगंज अनाज मंडी के अधिकांश दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों को इस घनी आबादी वाले क्षेत्र से कम मांग के कारण स्थानांतरित करने का विरोध करते हैं। ये दुकानें इष्टतम स्थान के साथ पिछड़ जाती हैं और आसपास के क्षेत्र की तरह अनुपयुक्त मानी जाती हैं। खुदरा दुकानों के प्रभुत्व की विशेषता है। मांग और आपूर्ति की अधिक चिंता से उस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम हो जाता है।

तेजी से शहरीकरण, गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण और बेरोजगारी जैसी वर्तमान शहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए शहरों और शहरी क्षेत्रों के सतत विकास और पुनर्विकास के लिए विभिन्न कॉल किए गए हैं। शहरी भूमि उपयोग योजना इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक अधिक प्रभावी उपकरण के रूप में पेश की जाती है।

नगरीय क्षेत्र अलवर की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या एवं योजनाओं का क्रियान्वयन :-

मानव संस्थान के किसी भी अन्य रूप की तरह योजना प्रणाली और अभ्यास को एक स्टीरियोटाइपिक वैचारिक मॉडल पर नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि आज दुनिया के सामने आने वाली सतत विकास चुनौतियों को दूर करने में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए मानवीय कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए कल्पना की जानी चाहिए।

शहरीकरण के परिणामस्वरूप शहर के पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों (भूमि, वायु, जल, मिट्टी और जंगल) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए अलवर को भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरी केंद्रों में शामिल किया गया है, जहां ठोस कण पदार्थ (एसपीएम) हैं। और २ स्तर गंभीर पाए गए (खुल्लर, 2008)। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में पत्थर और संगमरमर काटने और पॉलिश करने वाले उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, यातायात की बढ़ती संख्या शामिल हैं।



ध्वनि प्रदूषण के बाद होप सर्कस क्षेत्र में धातु आधारित और तेल, घानी उद्योग अगोचर ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। इसके अलावा, अपर्याप्त और खराब स्वच्छता, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट निपटान सेवाओं के कारण खुले में शौच, कचरे के ढेर और सड़कों पर कचरे से भरे सीवरेज का अतिप्रवाह पर्यावरणीय जटिलताओं को बढ़ाता है। जीर्ण-शीर्ण, अप्रचलित संरचनाओं की बढ़ती संख्या के कारण आंतरिक भाग शहरी क्षय की समस्या का सामना कर रहा है। आंतरिक शहर नवीनीकरण कार्यक्रम शहर और आंतरिक भाग की विशिष्टता को बहाल करके इन संरचनाओं को और अधिक क्षय और संरक्षित कर सकता है।

आवारा जानवर सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, यहां तक कि सड़कों के बीच में बैठना निवासियों या आगंतुकों के लिए समस्या पैदा करता है, जबकि वाहन चलाते समय वे अग्रणी दुर्घटनाओं में बाधा डालते हैं, इस ग्रामीण-शहरी संस्कृति को विकास को बढ़ावा देने के लिए बसने की जरूरत है। बाहरी भाग संरचनाओं के विरल विकास के बाद अनुचित विकसित बुनियादी ढाँचे के कारण सामाजिक अपराधों, यानी चोरी, डकैती, बलात्कार के मामले, जुआ, हत्या, दुर्घटना आदि की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

इस प्रकार के वातावरण में लोग हमेशा गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव और तनाव में रहते हैं। सड़कों पर रोशनी, सड़कों का उचित रखरखाव, पुलिस की गश्त लगाकर इन क्षेत्रों में शहरी वातावरण में सुधार किया जा सकता है।

व्लॉगिंग के ऑनलाइन चलन और कम खोजे गए चलन की खोज ने कई प्राकृतिक आवासों और जानवरों और पक्षियों के घूमने के स्थलों की खोज की है, किसी भी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण और प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया है। इसकी आवश्यकता है वनों के रूप में इन हरित वरदानों के संरक्षण के लिए एक घंटा; अन्यथा भविष्य में शहर का पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन निश्चित रूप से संकट में पड़ जाएगा। इसके लिए, तलहटी क्षेत्रों को कवर करने वाली एक पुनर्पौषण योजना मौजूदा स्थिति में सुधार कर सकती है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में कोई भी विकास गतिविधियाँ पर्यावरण के साथ-साथ पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य और अनुकूल होनी चाहिए। मास्टर प्लान के साथ-साथ विकास योजना में परिकल्पित ग्रीन बेल्ट के विकास को जमीनी स्तर पर तत्काल कार्यान्वयन की आवश्यकता है और प्रमुख सड़कों और परिधीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर दी गई है।

सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता :-

इस सीमित सफलता का मुख्य कारण मास्टर प्लान और अन्य विकास योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी है। जनता ही अपनी समस्याओं को पहचान सकती है और खुद को और अपने अलवर को प्राथमिकता दे सकती है, स्थानीय लोगों की तुलना में सरकारी अधिकारियों की तुलना में समस्याओं को प्राथमिकता देना और समस्याओं का बेहतर समाधान किया जा सकता है।

शहरी भूमि का डिजिटल मानचित्रण :-

शहरी भूमि उपयोग योजना को प्रौद्योगिकी संचालित, संसाधन क्षमता का आकलन, शहरी क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता और खपत की आवश्यकता है। शहरी सूचना प्रणाली (यूआईएस) उपग्रह डेटा और जीआईएस तकनीकों का उपयोग करके विषयगत मानचित्रों की तैयारी और एकीकरण के माध्यम से विकास में मदद करती है।

महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे और उनके समाधान :-

नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि अनेक पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न करती है। कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों और उनके समाधानों पर नीचे चर्चा की जा सकती है:

1. झोंपड़ी विकास

बड़े और छोटे शहरों (शहरी क्षेत्रों) के भीतर के क्षेत्र जिनकी सामाजिक और बुनियादी जरूरतें नहीं हैं, उन्हें स्लम कहा जाता है। ये मलिन बस्तियाँ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच की कमी और आवास की कमी के कारण हैं।

वे घिसे-पिटे डिब्बों, खाली तिरपालों, छतों, जूट के थैलों आदि से अपना घर बनाते हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में भीड़भाड़ है, इन सुविधाओं में प्रकाश, जलापूर्ति, पानी, सड़क, शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है। मलिन बस्तियाँ कई पर्यावरणीय समस्याओं का केंद्र बन जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है:

(में) ये उथले क्षेत्र अपने कचरे का अनौपचारिक तरीके से निपटान करते हैं जो हवा और पानी को प्रदूषित करता है।

(द्वितीय) जल प्रदूषण से टाइफाइड, हैजा, आंतों का बुखार और आंत्रशोथ जैसी बीमारियाँ होती हैं।

(पपप) अनौपचारिक कचरे के ढेर और खुले सीवर रोग फैलाने वाली बीमारियों जैसे मक्खियों, मच्छरों आदि के विकास के क्षेत्र बन जाते हैं। यह न केवल अनौपचारिक बस्तियों में बल्कि आस-पास के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। इसलिए, उपरोक्त पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए, सार्वजनिक सेवाओं जैसे प्रकाश व्यवस्था, पानी की आपूर्ति, पानी, शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान के साथ अनौपचारिक बस्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए।

2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र बहुत सारी सामग्री का उपयोग करता है और साथ ही बहुत अधिक ठोस अपशिष्ट भी पैदा करता है। ठोस कचरे में नगर निगम का कचरा, औद्योगिक कचरा, खतरनाक कचरा आदि शामिल हैं। बढ़ती आबादी के साथ ठोस कचरे का उत्पादन बढ़ता है। जब इस ठोस कचरे को लंबे समय तक फेंक दिया जाता है, तो इससे दुर्गंध और जहरीली गैसों निकलती हैं और फिर जानवरों की कई पीढ़ियाँ विभिन्न बीमारियों को जन्म देती हैं।

उत्पादित गैसों वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं, मलबे से सतह का अपवाह जल प्रदूषण का कारण बनता है और वैक्टर विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। उपरोक्त पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए, अधिक उपयुक्त अपशिष्ट निपटान विधि का उपयोग किया जाना चाहिए या जीवित, निर्जीव और पुनर्चक्रण योग्य कचरे का पुनर्चक्रण या निपटान किया जाना चाहिए।

3. प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके

भीड़भाड़ और महंगे जीवन यापन के कारण शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों (जैसे पानी, ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, वन उत्पाद आदि) का उपयोग बहुत अधिक है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग भी हो रहा है जिसकी क्षतिपूर्ति तेजी से बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में कुछ गंभीर समस्याएँ हैं। पीने के पानी की कमी विशेष रूप से भूजल, वन उत्पादों की कमी, अत्यधिक बिजली की खपत के कारण बिजली की कटौती आदि।

4. खुली जगह की उपलब्धता

शहरों के तेजी से विकास और भीड़भाड़ के कारण, पार्कों, खेल के मैदानों और मनोरंजन केंद्रों के लिए खुली जगहों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ है। इससे मुक्त और स्वच्छ हवा और खेलने और मनोरंजन के लिए जगह की कमी हो जाती है।

5. वायु प्रदूषण

शहरी क्षेत्रों में हवा कई मानवजनित गतिविधियों, बड़े पैमाने पर यातायात, उद्योगों आदि के कारण प्रदूषित होती है। ये गतिविधियाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक रासायनिक वाष्प, कण, जहरीली धातु आदि जैसे प्रदूषकों को छोड़ती हैं। कई स्वास्थ्य जोखिमों को कम कर सकता है।

6. ध्वनि प्रदूषण

कारों, वाहनों, सार्वजनिक कार्यों, उद्योगों आदि द्वारा उत्पन्न शोर शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है जिससे मानसिक और शारीरिक बीमारियाँ होती हैं।

7. नगर नियोजन कानूनों का उल्लंघन

यादृच्छिक शहरीकरण शहरी बस्तियों की स्थापना के लिए स्थापित नियमों के उल्लंघन की ओर जाता है जहाँ कोई स्वस्थ और आरामदायक जीवन जी सकता है। बिल्ट-इन स्ट्रक्चर किसी विशिष्ट लोकेशन इंडेक्स या प्लोर एरिया का अनुपालन नहीं करते हैं।

8. पानी के पाइप काटना

राष्ट्रीयता की भावना के बिना बड़ी संख्या में गरीब और ग्रामीण लोगों का पलायन, बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट, अनियोजित बस्तियाँ आदि को शहरी क्षेत्रों में डंप करना जल-जमाव और जल प्रवाह के लिए समस्या पैदा करता है।

9. यातायात और तैरते लोग

शहरी क्षेत्रों में काम की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की भारी आमद यातायात और सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा करती है।

10. असामान्य तापमान वृद्धि

शहरी क्षेत्रों में बड़ी इमारतों का अनौपचारिक निर्माण सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है और दोपहर में गर्मी की लहरें छोड़ता है जो जलवायु के तापमान को बढ़ाता है।

निष्कर्ष :-

राजस्थान सरकार ने अलवर शहर को एक गतिशील शहरी विकास केंद्र में बदलने के लिए विशेष चिंता दिखाई। हालांकि, अलवर को एक समावेशी और गतिशील शहरी विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के सरकार के लक्ष्य के साथ खड़े नहीं होने के कारण, अलवर शहर के विकास के मौजूदा रुझान राज्य के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं। कार्यान्वयन के बिना योजना बनाना ईंधन के बिना वाहन की तरह है। विश्लेषण शहर में उपलब्ध शहरी सुविधाओं के स्तर पर प्रकाश डालता है। शहरी नियोजन और कार्यान्वयन के स्तर के संबंध में जमीनी स्तर पर वास्तविकता नहीं मिली है। सभी उपायों और सावधानियों को केवल कागजों पर ही लागू किया जाता है, बजाय असलियत।

संदर्भ सूची :-

1. बेरी, बीजेएल (1961). शहर का आकार वितरण और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन।
2. गेडेस, पी. (1949). इवोल्यूशन विलियम्स और नॉरगेट, लंदन में शहर।
3. राजस्थान सरकार, मास्टर प्लान, 2014, जयपुर
4. शर्मा, केडी (1992)। "एक हिमालयी राज्य में शहरीकरण के पैटर्न और प्रक्रियाएं: हिमाचल प्रदेश (भारत) 1881-1981 का एक केस स्टडी", भारतीय भूगोलवेत्ता संस्थान वॉल्यूम 14, संख्या 1, पीपी.1-12 के लेनदेन।
5. अलवर का मास्टर प्लान (2001, 2011, 2021)